बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 150 ● नई दिल्ली ● शनिवार 28 मार्च 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मिले एलजी तरनजीत संधू, दिल्ली के विकास पर हुई चर्चा

नई दिल्ली। एलजी तरनजीत सिंह संधू ने शुक्रवार को भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। एलजी ने एक्स पर लिखा, अपने मित्र और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मिलकर खुशी हुई। गोर उन राजनयिकों में से एक थे जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली के 23वें उपराज्यपाल के रूप में संधू के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था। पूर्व राजनयिक संधू को संयुक्त राज्य अमेरिका के मामलों के सबसे अनुभवी विशेषज्ञों में से एक माना जाता है। उन्होंने वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास में कई बार अपनी सेवाएं दीं और फरवरी 2020 से जनवरी 2024 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत रहे।

'आत्मनिर्भरताके प्रयासों के बावजूद भारत की ऊर्जा आयात पर निर्भरता बढ़ी - जयराम रमेश

नई दिल्ली । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को ऊर्जा आयात पर बढ़ती निर्भरता को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में देश प्रमुख ईंधन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता से और दूर चला गया है। श्री रमेश ने एक बयान में कहा कि 2014-15 से 2024-25 के बीच कचे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता 84 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इसी अवधि में एलपीजी आयात पर निर्भरता 46 प्रतिशत से बढ़कर 62 प्रतिशत तक पहुंच गयी है।उन्होंने तंज कसते हुए कहा, यह सब तब हो रहा है जब नारा आत्मनिर्भरता का दिया गया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में प्राकृतिक गैस उत्पादन की स्थिति और भी अस्पष्ट बनी हुई है, जिसे उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान किए गए दावों से जोड़ा। उन्होंने याद दिलाया कि 26 जून 2005 को श्री मोदी ने घोषणा की थी कि गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (जीएसपीसी) ने कृष्णा-गोदावरी बेसिन के गहरे समुद्र में देश के सबसे बड़े गैस भंडार की खोज की है, जिसे भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाला बताया गया था। श्री रमेश ने हालांकि यह आरोप लगाया कि बाद की जांचों में ये दावे गलत साबित हुए। उन्होंने कहा, 2011 से 2016 के बीच कैग की पांच रिपोटरं में इसे 20,000 करोड़ रुपये का घोटाला बताया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अगस्त 2017 में जीएसपीसी का ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में विलय कर इस मुद्दे को दबा दिया गया। उन्होंने टिप्पणी की, मोदी द्वारा जिस गैस का बड़े स्तर पर वादा किया गया था, वह केवल'गैसही बनकर रह गई। यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश की ऊर्जा सुरक्षा और आयात निर्भरता को लेकर राजनीतिक बहस तेज है, खासकर तब जब बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत अभी भी विदेशी स्रोतों पर काफी हद तक निर्भर है। दूसरी ओर, सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ाने, ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और दीर्घकालिक रणनीति के तहत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसे कदमों का लगातार उल्लेख करती रही है।

दिल्ली विधानसभा में भाजपा एमएलए की बड़ी मांग, राजधानी का नाम बदलकर किया जाए इंद्रप्रस्थ

नई दिल्ली ।शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र में भाजपा की एक विधायक ने दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग उठाई। वज़ीरपुर से भाजपा विधायक पूनम शर्मा ने सदन में विशेष उल्लेख के माध्यम से अपनी बात रखी और कहा कि इससे शहर अपनी जड़ों से जुड़ सकेगा। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से आग्रह करती हूं कि वे विधानसभा में दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने का प्रस्ताव पारित करें और इसे केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजें। भाजपा विधायक ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी का नाम बदलना देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित होगा। इसी तरह की मांग पहले चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में उठाई थी। इसी बीच, शर्मा ने कहा कि दिल्ली का गौरवशाली अतीत महाभारत काल से जुड़ा है, और इस बात के ठोस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं कि यह शहर पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था और दिल्ली नाम बहुत बाद में पड़ा। उन्होंने कहा कि इंद्रप्रस्थ नाम हमें उस युग की याद दिलाता है जब हमारा देश स्वर्णपक्षी के नाम से प्रसिद्ध था।

नया नाम देश को एक महान सांस्कृतिक पहचान दिलाएगा। शर्मा ने जोर देकर कहा कि रेखा गुप्ता सरकार का मानना है कि दिल्ली में न केवल आधुनिक बुनियादी ढांचा होना चाहिए बल्कि यह सनातन धर्म की महिमा में भी निहित होना चाहिए। दिल्ली के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास रहे बंगले का वीडियो सार्वजनिक करने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि यह 'शीश महल' केवल एक इमारत नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, अहंकार और जनता के साथ विश्वासघात का जीता-जागता प्रमाण है। दिल्ली के लोक निर्माण (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख केजरीवाल के मुख्यमंत्री के रूप में आधिकारिक निवास रहे बंगले का एक वीडियो 'धुरंधर 3' शीर्षक से बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए उन्हें दिल्ली का रहमान डकैत बताया।

संसद - लोकसभा में पेश हुआ जन विश्वास विधेयक, कांग्रेस सांसदों ने किया विरोध; बिल में क्या हैं प्रावधान?

नई दिल्ली । सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया। इसका मकसद छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और नियमों आसान बनाना है। इससे कारोबार करना आसान हो सकेगा। विधेयक को वाणिय एवं उद्योग राय मंत्री जितिन प्रसाद ने पेश किया। इसमें चयन समिति की सिफारिशों को शामिल किया गया है। इस विधेयक का मकसद कुछ कानूनों में बदलाव करने के छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाना और नियमों को सरल बनाना है, ताकि भरोसे पर आधारित शासन को बढ़ावा मिले और लोगों का जीवन और कारोबार करना आसान हो सके।

कांग्रेस सांसदों ने किया विधेयक का विरोध

कांग्रेस सांसद कडियम काव्या और जीके पदवी ने इस विधेयक का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है। पदवी ने सरकार से अपील की कि इस विधेयक को फिर से चयन समिति या किसी संसदीय समिति के पास भेजा जाए। उन्होंने कहा, यह एक प्रशासनिक चूक है। विधेयक मनमाना है और इससे भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। इसलिए इसकी दोबारा जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि चयन समिति की रिपोर्ट में असहमति दर्ज करने का विकल्प दिया गया है।

वाणिय एवं उद्योग राय मंत्री ने क्या कहा?

जितिन प्रसाद ने कहा, इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें केवल छोटे अपराधों को ही अपराध की श्रेणी से हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा, यह विधेयक छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करेगा। साथ ही जुर्माना और सजा को अपराध की गंभीरता के हिसाब से तय किया जाएगा और अपील करने की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। इससे लोगों के लिए जीवन जीना और कारोबार करना आसान हो जाएगा। उन्होंने बताया, इस विधेयक के तहत 23 मंत्रालयों की ओर से लागू 79 केंद्रीय कानूनों के कुल 784 प्रावधानों में बदलाव प्रस्तावित है। इनमें 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव है, ताकि कारोबार करना आसान हो सके, जबकि 67 प्रावधान लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए बदले जाएंगे। इस विधेयक को 17 मार्च को चयन समिति की सिफारिशों को शामिल करने के लिए लोकसभा से वापस ले लिया गया था, ताकि इसे फिर से पेश किया जा सके। वाणिय एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 18 मार्च 2025 को यह विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, जिसके बाद इसे चयन समिति को भेज दिया गया था। यह प्रक्रिया 2023 के जन विश्वास कानून की सफलता पर आधारित है, जिसमें कई कानूनों में छोटे अपराधों को खत्म किया गया था। 11 अगस्त 2023 को लागू इस कानून के तहत 19 मंत्रालयों के 42 केंद्रीय कानूनों में 183 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया था।

लोकसभा: तीन विधेयकों पर जेपीसी की रिपोर्ट के लिए बढ़ी समय सीमा, जेल जाने पर व्यक्ति को पद से हटाने का प्रावधान

नई दिल्ली । लोकसभा ने शुक्रवार को तीन अहम संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश करने की समय सीमा बढ़ा दी। अब यह रिपोर्ट 2026 के मानसूत्र सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन तक पेश की जाएगी। इन विधेयकों में संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025; जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार, 2025 शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद अपराजिता सारंगी ने सदन में इस समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। इन प्रस्तावित संशोधनों में यह प्रावधान भी किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तारी के बाद जेल जाता है, तो वह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री पद पर नहीं रह सकेगा। साथ ही किसी आरोपी नेता को गिरफ्तारी के तीस दिनों के भीतर जमानत लेनी होगा। वरना 31वें दिन उसे पद से हटना होगा और ऐसा न होने पर वह अपने पद के लिए स्वत अयोग्य हो जाएगा। इससे पहले नवंबर में संसद ने इन तीनों विधेयकों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपराजिता सारंगी को समिति का अध्यक्ष बनाया। इस समिति में लोकसभा और रायसभा के कुल 31 सदस्य शामिल हैं। लोकसभा से रविशंकर प्रसाद, भर्तृहरि महताब, सुप्रिया सुले और असदुद्दीन ओवैसी जैसे सदस्य शामिल हैं। वहीं, रायसभा से बृजलाल, उज्ज्वल निकम, सुधा मूर्ति और अन्य सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के सदस्यों ने इस समिति में हिस्सा नहीं लिया है। संयुक्त समिति इन तीनों विधेयकों का विस्तार से अध्ययन करेगी और चर्चा के बाद अपनी सिफारिशें संसद को सौंपेगी।

न्यायिक रिक्तियों में देरी बर्दाश्त नहीं - सीजेआई ने सभी हाई कोर्ट को लिखा पत्र, महिला जजों को लेकर कही ये बात

नई दिल्ली । देश की न्याय व्यवस्था में तेजी लाने की दिशा में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। सीजेआई ने देश के सभी उच न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखा है। उन्होंने निर्देश दिया है कि जजों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया में अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पत्र की सबसे खास बात महिला जजों की नियुक्ति को लेकर इुद्ध का सख्त रुख है। सीजेआई सूर्यकांत ने अपने पत्र में जिक्र किया है कि उच न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब भी काफी कम है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट कॉलेजियम को महिला जजों की नियुक्ति को अपवाद के तौर पर नहीं, बल्कि सामान्य नियम के रूप में देखना चाहिए। मेधावी महिला वकीलों को बेंच का हिस्सा बनाना केवल संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता लाने के लिए अनिवार्य है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बताया कि जिला अदालतों में महिला न्यायिक अधिकारियों की संख्या लगभग 36.3 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि जब निचली अदालतें इतना मजबूत है, तो इसका असर उच न्यायपालिका में भी दिखना चाहिए। उन्होंने हाईकोर्ट कॉलेजियम से आग्रह किया कि वे अपना दायरा बढ़ाएं। सीजेआई सूर्यकांत ने सुझाव दिया कि हाईकोर्ट उन महिला वकीलों के नामों पर भी विचार करें जो उनके रायों से ताल्लुक रखती हैं लेकिन वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रही हैं। अक्सर देखा गया है कि जज के रिटायर होने के महीनों बाद तक पद खाली रहता है। इस पर भी सीजेआई ने सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि वैकेंसी होने का इंतजार न करें; पद खाली होने से पहले ही नामों की सिफारिश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जानी चाहिए।

28-29-30-31 मार्च तक भारी बारिश मचाएगी तांडव, आईएमडी ने इन रायों में जारी किया हाई अलर्ट

नई दिल्ली । देशभर में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। प्री-मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ कई रायों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। अब देश में प्री-मानसून तेवर दिखाएगा। इसी बीच आईएमडी ने 28, 29, 30 और 31 मार्च को देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

उत्तर-पश्चिम भारत में तेज असर

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में प्री-मानसून का असर सबसे यादा देखने को मिलेगा। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। इस दौरान 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, धूल भरी आंधी आने और बिजली गरजने की चेतावनी जारी की गई है।

दक्षिण भारत में भी बारिश का अलर्ट

दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी, माहे, कराईकल और यनम में भी 28 से 31 मार्च के बीच भारी बारिश की संभावना जताई गई है। यहां 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।

पश्चिम भारत में भी बदलेगा मौसम

पश्चिम भारत के मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात में भी प्री-मानसून का असर दिखेगा। इन क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ धूल भरी आंधी, बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है।

उत्तर-पूर्व भारत में भी चेतावनी

असम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

लोगों के लिए सलाह

मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने, खुले इलाकों में जाने से बचने और बिजली गिरने के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। प्री-मानसून की यह सक्रियता आने वाले दिनों में मौसम को और अधिक अस्थिर बना सकती है, जिससे कई रायों में जनजीवन प्रभावित होने की

धोखेबाज पाकिस्तान की कुंडली

पश्चिम एशिया में संकट पर केन्द्र द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने देश में पर्याप्त तेल और गैस भंडार होने और स्थिति नियंत्रण में होने का भरोसा दिया। विपक्षी दलों ने संकट के इस दौर में सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की लेकिन साथ ही उसने अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता में पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका पर चिंता जताई। विपक्ष की चिंताओं का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पाकिस्तान पर तीखा व्यंग्य कसते हुए कहा कि भारत वैश्विक भूराजनीति में 'दलाल राष्ट्र' के रूप में कार्य नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की नौटंकी नई नहीं है और यह 1981 से जारी है। अमेरिका वर्षों से तेहरान के साथ सम्पर्क बनाए रखने के लिए इस्लामाबाद का इस्तेमाल एक चैनल के रूप में करता आया है। विदेश मंत्री की यह टिप्पणियां ऐसी खबरों के बाद आई है जब पाकिस्तान वाशिंगटन और तेहरान के बीच संदेशों को सक्रिय रूप से पहुंचाने की भूमिका निभा रहा है। अमेरिका ने ईरान को 15 सूत्री प्रस्ताव भी पाकिस्तान के माध्यम से ही भेजा है। यद्यपि ईरान ने अमेरिका के 15 सूत्री प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के इतिहास के पन्ने पलटें तो उसका पूरा इतिहास धोखे और दलाली से भरा हुआ है। पाकिस्तान अलग राष्ट्र बनने के बाद से ही दलाली करता आया है। जब-जब पाकिस्तान ने शांति दूत का चोला पहना तब-तब दुनिया ने खून-खराबा और विश्वासघात देखा है। कई रक्षा विशेषज्ञों ने समय-समय पर पाकिस्तान के दोगलेपन की ऐसी कहानियां सुनाई हैं जिससे पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। यही कारण है कि आज पाकिस्तान पर कोई भी देश भरोसा नहीं करता। पाकिस्तान ने हमेशा ही अपने अवाम को धोखे में रखा और उसके हुक्मरानों ने अपने ही देश को जमकर लूटा। उसके धोखे का शिकार पड़ोसी देश भी हुए। 9/11 के हमले के बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति बुश पर युद्ध उन्माद छाया हुआ था और अमेरिका ने पाकिस्तान को तालिबान से अलग न होने पर उसे पत्थर युग में वापिस भेजने की धमकी दी थी, तब तत्कालीन पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने यू-टर्न लेकर अमेरिका की गोद में बैठना बेहतर समझा था। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में आतंकवाद की खेती करने वाले पाकिस्तान को अपना साथी बना लिया। यह कितना हास्यास्पद था कि एक जेहादी देश को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में आगे कर दिया गया। जबकि अमेरिका जानता था कि ट्विन टॉवर पर हमला करने वाले आतंकवादियों में कुछ को ट्रेनिंग भी पाकिस्तान ने ही दी थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर धावा बोल दिया और आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान पर डॉलरों की बरसात कर दी। पाकिस्तान ने एक तरफ अमेरिकी डॉलरों का इस्तेमाल आतंकवाद को सींचने के लिए किया तो दूसरी तरफ अमेरिका को धोखे में रखकर तालिबान को संरक्षण दिया। अमेरिका चाहता तो पाकिस्तान को मलयट में बदल सकता था, पर अमेरिका को लगता था कि अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन और अन्य से प्रतिशोध के लिए उसे पाकिस्तान की जरूरत है। 20 वर्ष तक अमेरिका तोरा-बोरा की पहाड़ियों में खाक छानता रहा, उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। पाकिस्तान दोहरापन अपनाता रहा। अफगानिस्तान में अमेरिकी विफलता का कारण पाकिस्तान ही रहा। अंततः अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपे ओसामा बिन लादेन को मार डाला। तब अमेरिका को अहसास हुआ कि लादेन को अपने यहां छिपाने वाले पाकिस्तान का सच क्या है। रक्षा विशेषज्ञ मेजर गौरव आर्या ने 2020 के यूएस-तालिबान दोहा शांति समझौते का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की गद्दारी की कुंडली खोली। उन्होंने बताया कि आज तालिबान पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों करता है। पाकिस्तान ने तालिबान के शीर्ष नेता मुल्ला बरादर को शांति वार्ता के नाम पर पाकिस्तान बुलाया। कहा गया कि पाकिस्तानी सबसे मेहमान-नवाज कौम है लेकिन जब मुल्ला बरादर वहां पहुंचा, तो पाकिस्तानियों ने उसे 9 साल तक जेल में बंद रखा और बेरहमी से टॉर्चर किया।- मेजर ने बताया कि तालिबान नेतृत्व इस धोखे को कभी नहीं भूला। तालिबान के एक पूर्व राजदूत ने अपनी किताब में पाकिस्तानियों को 'दो-मुंहे' लोग कहा है, जिनकी जुबान पर कुछ और होता है और दिल में कुछ और। पाकिस्तान ने सोचा था कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनवाकर वह वहां अपना पांचवां सूबा (राज्य) स्थापित कर लेगा और वहां की सत्ता को रिमोट कंट्रोल से चलाएगा लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। आज वही तालिबान, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) का खुलकर समर्थन कर रहा है और टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान की सेना को उन्हीं की जमीन पर गाजर-मूली की तरह काट रहे हैं। जो पाकिस्तान दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहा था, आज वह खुद उसमें गिरकर लहूलुहान है। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के पीछे पाकिस्तान का अपना एक डर भी है। पाकिस्तान फौज के अन्दर एक बड़ी संख्या शिया मुसलमानों की है। ईरान के लिए ये शिया सैनिक बहुत मायने रखते हैं और पाकिस्तान इस बात को लेकर खौफ में है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को डर है कि अगर उन्होंने अमेरिका के दबाव में आकर ईरान के खिलाफ कोई भी कदम उठाया, तो पाकिस्तानी फौज के अंदर मौजूद शिया सैनिक अपनी ही स्टेट (सरकार) के खिलाफ हथियार उठा सकते हैं। यह पाकिस्तान के लिए एक गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा कर देगा। अब पाकिस्तान की हालत एक ऐसे 'चुंगी नाके' जैसी है जो दूसरों के झगड़े में अपनी कमीशन (10-5 प्रतिशत) ढूंढ रहा है। न उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है, न कोई हैसियत। जो देश अपने पाले हुए आतंकियों से नहीं निपट पा रहा और जहां फौज के अंदर ही विद्रोह का डर सता रहा हो, उसका विश्व शांति की बात करना 21वीं सदी का सबसे बड़ा मजाक है। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान के साथ तुर्की और मिस्र भी मध्यस्थता के दावे कर रहे हैं, जबकि मिस्र ईरान से नफरत करता है और तुर्की भी ईरान का विरोधी है। तुर्की वही देश है जिसने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ड्रोन दिए थे। पाकिस्तान ने 1971 में बांग्लादेश में जो नरसंहार किया था उसे आज तक बांग्लादेश की जनता भूल नहीं पाई।

युद्ध से सबक - वैकल्पिक ऊर्जा को अपनाएं

पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते दुनिया भर में तेल और गैस संकट गम्भीर होता जा रहा है। यद्यपि केन्द्र की मोदी सरकार ने देश में पैट्रोल और गैस की सप्लाई निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस सबके बावजूद संकट की आशंका से लोगों को गैस एजेंसियों के सामने लम्बी कतारें देखी गईं। देश के कई राज्यों के बड़े शहरों अहमदाबाद, मुम्बई, बेंगलुरु आदि में पैट्रोल के खत्म होने की आशंका के चलते वाहन चालकों की लम्बी कतारें देखी गईं। युद्ध ने प्रभावी रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है इससे तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। कच्चे तेल की कीमत अब 109 डॉलर प्रति बैरल है, जो फरवरी के मध्य में 65 डॉलर थी। युद्ध जितना लम्बा चलेगा, कीमतों में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। तेल की कीमतों में इस तीव्र वृद्धि का मुद्रास्फीति पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। आपूर्ति में व्यवधान की आशंका से जूझ रहे वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें पहले ही भारत में 60 रुपये प्रति घरेलू और 144 रुपये प्रति वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं के लिए बढ़ा दी गई है। हमारी एलएनजी का 40 प्रतिशत कतर से आता है, जिसने अपने गैस निर्यात संयंत्र बंद कर दिए हैं। तेल-गैस संकट के इस दौर में सरकार ने मार्च में ही पीएनजी (रसोई में पाइपलाइन गैस) के 3.5 लाख से अधिक कनेक्शन दिलाए हैं। अब देश में इस गैस के मात्र 1.65 करोड़ से अधिक उपभोक्ता हैं। देश की आबादी 147 करोड़ से अधिक है। उसमें 33 करोड़ एलपीजी (रसोई गैस) के उपभोक्ता हैं। दरअसल पीएनजी का तो बुनियादी ढांचा ही बेहद सीमित है। पाइपलाइन की सुविधा कुछ बड़े शहरों की गिनी-चुनी कॉलोनियों में ही मौजूद है। गैस की उपलब्धता को लेकर चिंता के कारण इंडक्शन स्टोव की खरीद में भारी उछाल आया है। खाना पकाने के लिए बिजली के उपयोग को बढ़ावा देना निरंतर रूप से आवश्यक है। इंडक्शन स्टोव अधिक ऊर्जा-कुशल होते हैं। उदाहरण के लिए, 8 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली का उपयोग करना गैस से सस्ता है। कम आय वाले परिवारों के लिए बचत कहीं अधिक होगी। उनके लिए बिजली की दरें कम हैं। कुछ राज्यों में प्रति माह 200-300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। युद्ध से भारत को सबक लेने की जरूरत है। इस संकट ने हमें सिखाया कि भारत के लिए यह अहम समय है कि वह ऊर्जा स्रोतों को अन्य देशों से अलग करने के लिए व्यापक योजना बनाए। "सही नीतिगत प्रोत्साहन से भारत को दीर्घकालिक रूप से अधिक स्थिर और सुरक्षित दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है।" देश में एक बार फिर बिजली के महत्व को दिखा दिया है। आने वाले समय में कृषि उत्पादों से बनने वाला एथनॉल रसोई गैस (एलपीजी) का विकल्प बन सकता है। इसके लिए विभिन्न संस्थानों में एथनॉल से चलने वाले कुकिंग स्टोव विकसित करने पर काम चल रहा है। एथेनॉल न केवल गाड़ियों के लिए, बल्कि अब घरों की रसोई के लिए भी एक सुरक्षित और सस्ता विकल्प बन सकता है। एथेनॉल आधारित चूल्हों के कुछ शुरुआती मॉडल तैयार कर लिए गए हैं। हालांकि, यह प्रोजेक्ट अभी बेहद शुरुआती चरण में है।

बिजली हमारे हर काम को शक्ति प्रदान करती है- हमारे घर, कारखाने, खेत, दफ्तर और परिवहन लेकिन अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्से कितनी बिजली का उपयोग करते हैं, यह हमें किसी देश के विकास के बारे में बहुत कुछ बताता है। भारत में बिजली का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता उद्योग (42 फीसदी) है-कारखाने और विनिर्माण संयंत्र। घरों में लगभग 26फीसदी बिजली का उपयोग होता है और कृषि में भी इसका बड़ा हिस्सा, लगभग 17फीसदी -मुख्य रूप से पानी के पंप और मशीनों को चलाने के लिए उपयोग होता है। दुकानें, कार्यालय और सार्वजनिक सेवाएं मिलकर लगभग 8फीसदी बिजली का उपयोग करते हैं, जबकि परिवहन में केवल 2प्रतिशत बिजली का उपयोग होता है। इससे पता चलता है कि भारत में कृषि के लिए अभी भी बहुत अधिक बिजली का उपयोग होता है और वाणिज्यिक सेवाओं के लिए कम। भारत तेजी से बदल रहा है। जैसे-जैसे अधिक लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और सेवाओं का विस्तार हो रहा है, कार्यालयों और दुकानों में बिजली की खपत बढ़ेगी, जबकि कृषि में इसकी हिस्सेदारी कम होगी। इसका अर्थ यह है कि भारत का बिजली का पैटर्न वैश्विक औसत के समान दिखने लगा है। अब देशवासियों को ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की ओर ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री की रूफटॉप सोलर योजना के तहत प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध है। देश में खाना पकाने के लिए बिजली का उपयोग करने से आयात पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी, भारत ने इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू उत्पादन में पहले ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। यहां एक प्रतिस्पर्धी उद्योग संरचना मौजूद है। लोकप्रिय मॉडलों के कई अच्छे इलेक्ट्रिक संस्करण अब बाजार में उपलब्ध हैं। उपभोक्ता यह जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की लागत कम है। भारत इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन रहा है। बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? एक व्यवहार्य निर्णय यह होगा कि एनसीआर से शुरू करते हुए, भावी तिथियों से सभी वाणिज्यिक वाहनों को इलेक्ट्रिक होना अनिवार्य कर दिया जाए इससे वाणिज्यिक वाहन संचालकों को बचत होगी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री की रूफटॉप सोलर योजना के तहत प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध है। देश में खाना पकाने के लिए बिजली का उपयोग करने से आयात पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी और इस आवश्यक वस्तु के लिए लोगों की असुरक्षा दूर हो जाएगी। अगर किचन एक बार पैनल लगाया जाता है तो वह कई वर्षों के लिए बिजली से मुक्त हो जाता है। इन घटनाक्रमों ने ऊर्जा सुरक्षा के महत्व को उजागर किया है। दशकों से हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए तेल और गैस के भंडारों की खोज में जुटे हैं लेकिन सफलता नहीं मिली है। भारत ऐसा देश है, जहां सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पनबिजली और परमाणु ऊर्जा का लगातार उत्पादन किया जा रहा है, लिहाजा लोग उनका प्रयोग भी कर रहे हैं। इसके बावजूद आयात पर हमारी निर्भरता और भी बढ़ गई है। तेल और गैस के आयात पर सालाना 100 अरब डॉलर से अधिक खर्च होता है और यह हमारे कुल आयात का 25-30 प्रतिशत है। सूर्य और पवन भारत को बहुत बड़ी ऊर्जा दे सकते हैं।

सम्पादकीय...

युद्ध के चलते दुनिया भर में 'ऊर्जा लॉकडाउन' का डर!

विश्व आज एक नए संकट के कगार पर खड़ा है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध ने मात्र 4 सप्ताह में वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला दिया है। 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज', जिससे दुनिया के 20 प्रतिशत तेल और एल.एन.जी. का परिवहन होता है, प्रभावी रूप से बंद हो गया है। ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड और कतर के रास लाफान एल.एन.जी. प्लांट पर हमलों से वैश्विक उत्पादन में 3.5 प्रतिशत की कमी आई है, जिसकी मुरम्मत में वर्षों लग सकते हैं। तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं, जबकि भारत जैसे आयात-निर्भर देशों में डीजल, एल.पी.जी. और बिजली की आपूर्ति पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में 'ऊर्जा लॉकडाउन' की चर्चा जोर पकड़ रही है। एक ऐसी स्थिति, जिसमें ईंधन राशनिंग, बिजली कटौती और औद्योगिक गतिविधियों पर अंकुश लग सकता है, ठीक कोविड जैसी आपात स्थिति की तरह। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आई.ई.ए.) के प्रमुख फतिह बिरोल ने इसे 'मेजर, मेजर थ्रैट' बताया है। होर्मुज बंद होने से न केवल तेल, बल्कि उर्वरक, हीलियम और सल्फर की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है, जो खाद्य उत्पादन और ए.आई. तकनीक तक को प्रभावित कर रही है। बांग्लादेश ने पहले ही ईंधन राशनिंग लागू कर दी है। श्रीलंका में अनिवार्य ऊर्जा अवकाश की घोषणा हुई है। भारत में भी पैट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, एल.पी.जी. सिलेंडर की आपूर्ति अनिश्चित है और बिजली संयंत्रों में कोयला-गैस का संकट गहरा रहा है। यदि युद्ध लम्बा चला तो 'ऊर्जा लॉकडाउन' वास्तविकता बन सकता है। यानी उद्योग बंद, परिवहन सीमित और घरेलू बिजली पर पाबंदी। यह न केवल मुद्रास्फीति बढ़ाएगा, बल्कि विकास दर को 1-2 प्रतिशत तक घटा सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि होर्मुज 2-3 महीने और बंद रहा तो वैश्विक मंदी अनिवार्य हो जाएगी। लेकिन संकट के बीच आशा की किरण भी दिख रही है। शांति वार्ता की संभावना बन रही है और इसमें पाकिस्तान की भूमिका अचानक केंद्र में आ गई है। खबरों के अनुसार, अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ के बीच इस्लामाबाद में संभावित शिखर वार्ता की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान ने 15 प्वाइंट प्रस्ताव अमरीका की ओर से ईरान तक पहुंचाया है, जिसमें होर्मुज खोलने, यूरेनियम संवर्धन सीमा और मुआवजे जैसे मुद्दे शामिल हैं। सवाल उठता है कि क्या युद्धविराम संभव है? कूटनीतिक विशेषज्ञों का मत विभाजित है। कुछ का मानना है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता एक 'टर्निंग प्वाइंट' साबित हो सकती है क्योंकि दोनों पक्ष थक चुके हैं। तेल की महंगाई के चलते अमरीका को भी घरेलू आर्थिक दबाव और इजराइल को क्षेत्रीय विस्तार की सीमा का सामना करना पड़ रहा है। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही जर्जर रही है। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट और स्टिमसन सैंटर के विश्लेषकों का कहना है कि यह युद्ध 'कोई स्पष्ट विजेता' नहीं देगा। इजराइल के हमलों से ईरान की ऊर्जा सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिनकी मुरम्मत में वर्षों लगेंगे। ईरान की ओर से जवाबी हमले अभी भी जारी हैं। यदि युद्धविराम हो भी गया तो भी 'दूसरे चरण' के मुद्दे जैसे कि परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और मुआवजा आदि बने रहेंगे।

ज़ेलों में विचाराधीन कैदी-न्याय से पहले सजा? क्या हम वास्तव में न्याय कर रहे हैं या एक और अन्याय को जन्म दे रहे हैं?

वैश्विक स्तरपर आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में जेल का उद्देश्य केवल अपराधी को दंडित करना नहीं, बल्कि उसे सुधारना और पुनर्वास के लिए तैयार करना भी होता है। परंतु जब जेलें स्वयं ही भय,बीमारी और उपेक्षा का केंद्र बन जाएं,तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हम वास्तव में न्याय कर रहे हैं या एक और अन्याय को जन्म दे रहे हैं? सलाखों के पीछे भी सेफ नहीं?, यह केवल एक भावनात्मक प्रश्न नहीं,बल्कि कठोर वास्तविकता का दर्पण है।अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुसार,कैदियों से उनका स्वतंत्रता का अधिकार तो छीना जा सकता है,लेकिन उनका जीवन, स्वास्थ्य और गरिमा का अधिकार नहीं। इसके बावजूद भारत सहित दुनियाँ के कई देशों में जेलों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह बताना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित नेल्सन मंडेला नियम (यू एन स्टैंडर्ड मिनिमम् रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स) स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए।उन्हें पर्याप्त भोजन,स्वच्छ पानी,स्वास्थ्य सुविधाएं और मानसिक स्वास्थ्य सहायता मिलनी चाहिए। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर इन सिद्धांतों और वास्तविकता के बीच गहरी खाई दिखाई देती है। जेलें, जो सुधार गृह मानी जाती हैं,अक्सर प्रताड़ना, हिंसा और उपेक्षा के केंद्र बन जाती हैं। यह स्थिति केवल विकासशील देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि विकसित देशों में भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं। साथियों बात अगर हम भारत में जेलों की भीड़-एक गंभीर संरचनात्मक संकट को समझने की करें तो,भारत की जेल व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या है,क्षमता से अधिक भीड़। कई राज्यों में जेलों की ऑक्यूपेंसी दर 150 प्रतिशत से लेकर 200 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। उदाहरण के तौर पर, दिल्ली की जेलों में 200 प्रतिशत तक कैदी भरे हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 150 प्रतिशत से अधिक है। इस भीड़ का सबसे बड़ा कारण है विचाराधीन कैदियों की अत्यधिक संख्या। आंकड़ों के अनुसार, भारत के लगभग 73.5 प्रतिशत कैदी ऐसे हैं जिनका अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है और वे केवल ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। यह स्थिति न्यायिक प्रणाली की धीमी गति और मामलों के लंबित रहने का सीधा परिणाम है। साथियों बात अगर हम विचाराधीन कैदी- न्याय से पहले सजा? इसको समझने की करें तो,विचाराधीन कैदी वह होते हैं जिन्हें अभी अदालत ने दोषी नहीं ठहराया है, फिर भी वे वर्षों तक जेल में बंद रहते हैं। यह स्थिति निर्दोषता की धारणा (प्रिसम्पशन ऑफ इनोसेंस) के सिद्धांत के विपरीत है। न्यायिक देरी के कारण कई कैदी अपने संभावित सजा से अधिक समय जेल में बिता देते हैं। यह न केवल उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा करता है।जेलों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों के लगभग 30-40 प्रतिशत पद खाली हैं। दिल्ली जैसी जगहों पर प्रति 200 कैदियों पर केवल एक डॉक्टर उपलब्ध है।इसका परिणाम यह होता है कि गंभीर बीमारियों का समय पर इलाज नहीं हो पाता। अस्वच्छता और भीड़भाड़ के कारण टीबी, एचआईवी और हेपेटाइटिस जैसी संक्रामक बीमारियां तेजी से फैलती हैं। वर्ष 2024 के पहले नौ महीनों में भारत में न्यायिक हिरासत में 1,558 मौतें दर्ज की गईं,यह आंकड़ा केवल संख्या नहीं, बल्कि एक गंभीर मानवीय संकट का संकेत है।इन मौतों के पीछे मुख्य कारण हैं,बीमारियां, आत्महत्याएं और चिकित्सा सुविधाओं की बहुत हद तक कमी। साथियों बात अगर हम छत्तीसगढ़ का मामला- एक राय, कई सवाल इसको समझने की करें तो छत्तीसगढ़ की जेलों में पिछले चार वर्षों में 285 कैदियों की मौत का मामला पूरे देश को झकझोर देने वाला है। इनमें से 90 मौतें केवल 2022 में हुईं और 66 मौतें जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच दर्ज की गईं। राज्य सरकार ने इन मौतों के पीछे आत्महत्या और गंभीर बीमारियों को कारण बताया है। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने जेलों में भीड़भाड़, डॉक्टरों की कमी और प्रशासनिक लापरवाही को संभावित कारण बताया है। यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं,तो यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। साथियों बात अगर हम न्यायपालिका की सक्रियता-सुधार की दिशा में कदम को समझने की करें तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जेलों की स्थिति पर ताजा आंकड़े प्रस्तुत करने का निर्देश 26 मई 2026 तक सबमिट करने को दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने जेलों की क्षमता भीड़भाड़ और महिला कैदियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विस्तृत विवरण मांगा है।यह कदम दर्शाता है कि न्यायपालिका इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। विशेष रूप से महिला कैदियों और उनके साथ रहने वाले बच्चों की स्थिति पर ध्यान देना एक सकारात्मक पहल है, क्योंकि यह वर्ग अक्सर नीति निर्माण में उपेक्षित रह जाता है। साथियों बात अगर हम मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्याएं- अदृश्य संकट इसको समझने की करें तो जेलों में मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ा लेकिन अनदेखा मुद्दा है। भीड़भाड़, पारिवारिक दूरी, सामाजिक कलंक और अनिश्चित भविष्य कैदियों को मानसिक रूप से कमजोर बना देता है।

यही कारण है कि जेलों में आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।ग्लोबल प्रिजन ट्रेंड्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में जेलों के भीतर आत्महत्या और हिंसा के मामलों में वृद्धि हुई है। यह केवल एक देश की समस्या नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर जेल सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। साथियों बात अगर हम संचार और मानवीय संपर्क - एक नई पहल इसको समझने की करें तो, कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए संचार के साधनों को बढ़ाना आवश्यक है।

इसी दिशा में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें कैदियों को अपने परिवारजनों से मुफ्त वीडियो और ऑडियो कॉल के माध्यम से संवाद करने की अनुमति देने की बात कही गई है।यह पहल कैदियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने और उनके सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में मदद कर सकती है। आधुनिक तकनीक का उपयोग जेल सुधार के लिए एक प्रभावी माध्यम बन सकता है। साथियों बात अगर हम सुधार की दिशा में आवश्यक कदम को समझने की करें तो जेल सुधार के लिए बहु आयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। सबसे पहले, न्यायिक प्रक्रिया को तेज करना होगा ताकि विचाराधीन कैदियों की संख्या कम हो सके। इसके लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट, डिजिटल सुनवाई और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना होगा।दूसरा, जेलों की क्षमता बढ़ाने और नए सुधार गृहों का निर्माण करना आवश्यक है। तीसरा, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना होगा,डॉक्टरों की भर्ती, नियमित स्वास्थ्य जांच और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना होगा।चौथा कैदियों के लिए कौशल विकास और शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने होंगे ताकि वे समाज में पुनः स्थापित हो सकें।पांचवां, जेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी, जिसमें स्वतंत्र निगरानी तंत्र की स्थापना महत्वपूर्ण होगी। साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य- एक साझा चुनौती को समझने की करें तो जेलों की बदहाल स्थिति केवल भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका,ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और फिलीपींस जैसे देशों में भी जेलों में भीड़भाड़, हिंसा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएं मौजूद हैं। हालांकि, कुछ देशों ने सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, नॉर्वे की जेल व्यवस्था को दुनिया में सबसे मानवीय माना जाता है, जहां कैदियों को पुनर्वास और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह मॉडल अन्य देशों के लिए प्रेरणा बन सकता है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि न्याय का असली अर्थ,जेलें किसी भी सभ्य समाज का दर्पण होती हैं।

यदि जेलों में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो यह पूरे समाज की विफलता का संकेत है। सजा का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्वास होना चाहिए। सलाखों के पीछे भी सेफ नहीं? यह प्रश्न हमें आत्ममंथन करने के लिए मजबूर करता है। क्या हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां न्याय केवल कागजों तक सीमित है, या हम वास्तव में एक मानवीय और न्यायपूर्ण व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं? समय आ गया है कि जेल सुधार को प्राथमिकता दी जाए,क्योंकि न्याय केवल अदालतों में नहीं, बल्कि जेलों की दीवारों केभीतर भी सुनिश्चित होना चाहिए।

लद्दाख की बेचैनी को समझना होगा

चन्द्रमोहन

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जिनके जीवन से प्रेरित फिल्म 3 इडियट्स बनी थी, रिहा होकर लेह लौट आए हैं। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गिरफ्तार किया गया था और जोधपुर जेल में रखा गया था। इस कानून के तहत किसी को अधिकतम 12 महीने हिरासत में रखा जा सकता है पर सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी की वकालत करने के बाद सरकार ने वांगचुक को 169 दिन के बाद रिहा कर दिया। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो बताया गया कि वह 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों' में संलिप्त है जिस बात से देश में शायद ही कोई सहमत हो। बहुत लोग तो उन्हें राष्ट्रीय खज़ाना मानते हैं। और अगर वह वास्तव में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे तो छोड़ा क्यों गया? सारे मामले से सरकार सही ढंग से नहीं निबटी और जो देश का एक प्रकार से सबसे शांत क्षेत्र था,लद्दाख, उसे बेचैन छोड़ दिया गया है। लद्दाख के बौद्ध और कारगिल के मुसलमान जो सदा एक दूसरे के विरोधी रहे हैं अब केन्द्र सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। जिस उपराज्यपाल के समय वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था को तो अब बदल दिया गया है। नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रिहाई का स्वागत करते हुए कहा है कि वहां 'आंदोलन और हिंसा की कोई जगह नहीं'। जहां तक हिंसा का सवाल है मैं उनकी बात से बिलकुल सहमत हूं। एक सभ्य समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए पर शांतिमय आंदोलन पर आपत्ति क्यों हो? आंदोलन करना हमारे मूल अधिकारों का हिस्सा है। हमने तो आज़ादी आंदोलन के द्वारा प्राप्त की थी। लद्दाख जैसा देश में कोई प्रदेश नहीं है। इसकी अद्भुत पर कठोर प्राकृतिक सुन्दरता मंत्रमुग्ध करने वाली है। ऊंचे पहाड़ हैं जिन पर कुछ नहीं उगता। इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। बीच में से शांत सिंधु और जांस्कर नदियां बहती हैं। 13000-14000 फुट की ऊंचाई पर घाटी स्थित है। आक्सीजन की कमी के कारण कई बाहरी लोगों को समस्या आती है। दुनिया की सबसे ऊंची झील पैंगोंग यहां है जिसको लेकर भारत और चीन के बीच तनातनी रहती है। क्षेत्र अपनी बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है इसलिए शांत है। इसके गोम्पा (मठ) के अंदर अत्यंत शांत वातावरण होता है और बाहर से गए व्यक्ति को लगता है कि वह इस शान्ति का उल्लंघन कर रहा है। पर यह क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील भी है क्योंकि चीन के साथ हमारी लम्बी सीमा है जहां लगातार झड़पें होती रहती हैं। हमें यहां के लोगों का अधिक सहयोग चाहिए जो गोली चलाने से नहीं मिलेगा। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार का है। 2019 में सरकार ने जम्मू-कश्मीर पर लागू धारा 370 तथा 35 निरस्त कर दिए थे। जब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर केन्द्रीय शासित प्रदेश बना दिया तो बौद्ध बहुसंख्या वाले लेह ज़िले ने जश्न मनाया। दशकों से उनकी यह मांग थी। लेकिन एक साल के अंदर-अंदर यह उत्साह ठंडा पड़ गया। 35 को निरस्त करने से क्षेत्र में रोज़गार, ज़मीन की मिल्कियत, और बाहरी लोगों के प्रवेश की आशंका को लेकर बेचैनी शुरू हो गई। पूर्व राजदूत पी स्टोबदन जो लद्दाखी हैं ने लिखा है, जश्न जल्द संवैधानिक संरक्षण की मांग में बदल गया। जो आज़ादी का जोश था उसकी जगह सुरक्षा की तलाश ने ले ली। बाहर से गए अधिकारी इस असुरक्षा की भावना को समझ नहीं सके और पहली बार नौबत यहां तक पहुंच गई कि गोली चलानी पड़ी, चार लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। अधिकारियों का कहना था कि सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ी। हो सकता है कि उनकी बात सही हो, पर ऐसी हालत ही क्यों बनने दी गई कि 'सेल्फ डिफेंस' में गोली चलानी पड़े? अगर लोगों की मांग व्यावहारिक नहीं है तो समझाने की ज़रूरत है। लद्दाख के लोगों की मूल मांगों में स्टेटहुड और संविधान के छठे शेड्यूल में शामिल करना है। वह अपनी ज़मीन पर अपना अधिकार सुरक्षित चाहते हैं। तीन लाख लोगों की आबादी वाले प्रदेश को स्टेटहुड नहीं दिया जा सकता। छठा शेड्यूल आदिवासी क्षेत्रों की व्यवस्था के लिए है जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम और असम में है। इसे उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों के लिए बनाया गया था। मणिपुर में यह अभी भी लागू नहीं किया गया। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में इसे देने का वादा किया था पर अब केन्द्र सरकार ने मन बदल लिया लगता है। इस पर फिर से विचार होना चाहिए। केन्द्र सरकार ने लद्दाख की खुले दिल से मदद की है। 2019 से पहले प्रदेश को केन्द्र से केवल 57 करोड़ रुपए वार्षिक मिलते थे जो अब बढ़ कर 6000 करोड़ रुपए हो गए हैं। इतनी भारी मदद के बावजूद असंतोष है। छह साल से वह लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित हैं। कोई निर्वाचित विधानसभा नहीं है। निर्णय दिल्ली से भेजे प्रशासक ले रहे हैं जिन्हें स्थानीय संवेदनाओं, ज़रूरतों और संस्कारों के बारे कोई ज्ञान नहीं है। ऊपर से बढ़ती बेरोज़गारी के कारण युवाओं में असंतोष है। परिणाम लेह जैसे शांतिमय शहर में लोगों के असंतोष का विस्फोट हो गया। इस सब के केन्द्र में सोनम वांगचुक हैं। वह अपनी मांगों के लिए दिल्ली तक पदयात्रा कर चुके हैं। लद्दाख पहुंच कर उन्होंने भूखहड़ताल शुरू कर दी जिसके 15वें दिन स्थिति हाथ से निकल गई और लेह में हिंसा भड़क उठी। सारे लद्दाख में बेचैनी फैल गई और लद्दाखी संगठनों ने केन्द्र के साथ बातचीत बंद कर दी। दूसरा परिणाम यह हुआ कि सोनम वांगचुक जो प्रदर्शन का चेहरा थे को रासुका के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हिंसा उकसाने का आरोप लगाया गया जिसका वह ज़बरदस्त प्रतिवाद करते हैं। वांगचुक ने ज़रूर अपने भाषणों में नेपाल के 'जैन ज़ैड' और 'अरब स्प्रिंग' का जिक्र किया था। बेहतर होता कि कोई उन्हें सावधान करता कि यह अनुचित है। वहां प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई। यह कितनी बड़ी त्रासदी थी यहत्सेवांग थरचिन की मौत से पता चलता है। वह फौजी था और उसका परिवार भी फौजी है। उसके पिता ने कारगिल की लड़ाई में हिस्सा लिया था। वह बताते हैं, यह कैसे हुआ गलवान के समय भी चीनियों ने ऐसे गोली नहीं चलाई थी। यहां तो पुलिस ने अपने लोगों पर गोली चला दी। आम तौर पर फ़ायरिंग पहले हवा में की जाती है फिर घुटनों के नीचे। मेरे बेटे को तो ज़मीन में लिटा कर गोली मारी गई। सेवांग का भाई कहता है कि मैं बता नहीं सकता कि वह कितना बड़ा देश भक्त था। उसने जल्दी रिटायरमेंट ले ली ताकि वह अपने तीनों बच्चों को सैनिक स्कूल भेज सके। लेह के पुलिस चीफ़ का कहना था कि अगर गोली न चलाते तो 'लेह को आग लग जाती। उनकी बात सेवांग के परिवार के कथन से मेल नहीं खाती। स्पष्ट है कि प्रशासन ने स्थिति को सही नहीं सम्भाला और जो क्षेत्र देशभक्तों का क्षेत्र है, जो सेना में लोग भेजता है, उसे नाराज़ कर दिया गया है। यह मणिपुर नहीं है जहां दो जातियां लड़ रही हैं। यहां संवाद कर और किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व दे कर मामला सुलझाया जा सकता था। हर जगह प्रशासनिक हथौड़ा नहीं चलना चाहिए। मेजर जनरल बख्शी जो कभी मोदी सरकार के प्रशंसक रहे हैं पर अब आलोचक हैं, ने बताया है, लद्दाख के लोग बहुत सीधे और प्यार वाले हैं। बौद्ध होने के कारण वह बहुत दयालु हैं फिर भी वह दुनिया में सबसे बढ़िया पहाड़ी सैनिक हैं। उन्होंने भारत की सुरक्षा के लिए जानें दी हैं। अशोक चक्र तक सम्मान उन्हें मिले हैं। लद्दाखी कहते हैं कि हम सेना के साथ साझेदारी करते हैं, उनके हर कदम पर साथ देते हैं। बहुत दुःख है कि ऐसे लोगों पर गोली चलाई गई। हमें तो इस नाज़ुक क्षेत्र,जिसकी सीमा चीन और पाकिस्तान से लगती है, के देशभक्त लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। हिंसा गलत है पर वहां तक नौबत नहीं आनी चाहिए थी।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने कदम ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साथ पैरामिना एस. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/39862)

विकास भवन में वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति की बैठक, विभागीय कार्यों की समीक्षा

कुशीनगर।

विकास भवन सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की ÷वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति÷ की बैठक विधान परिषद सदस्य डॉ. रतन पाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों को आवंटित बजट के सापेक्ष व्यय और कार्यों की गहन समीक्षा की गई। सभापति ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करें और जनहित से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता बरतते हुए समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विभागों को जिलाधिकारी के समन्वय से कार्ययोजना बनाकर शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा कुशीनगर को प्रदेश में उत्कृष्ट स्थान दिलाने के लिए प्रयास करने पर बल दिया। बैठक में शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवंटित धनराशि का लक्ष्य के अनुरूप उपयोग सुनिश्चित करने, नए शैक्षिक सत्र में छात्र पंजीकरण बढ़ाने, ड्रॉपआउट बच्चों का पुनः नामांकन कराने तथा ग्राम शिक्षा समिति, प्रधानों और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से नामांकन में वृद्धि करने के निर्देश दिए गए। साथ ही विद्यालयों में वार्षिक उत्सव आयोजित करने, कायाकल्प योजना के 19 बिंदुओं को पूर्ण करने, शौचालय एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण तथा सभी विद्यालयों के विद्युतीकरण पर जोर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग

की समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आयुष्मान भारत योजना के पात्र लाभार्थियों को शत-प्रतिशत आच्छादित करने और ग्राम स्तर पर कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी के प्रयासों से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की सराहना करते हुए समिति ने उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया। लोक निर्माण विभाग को सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए, जबकि विद्युत विभाग को रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, विद्युत चोरी पर सख्ती से कार्रवाई करने और सभी प्राथमिक विद्यालयों का विद्युतीकरण कराने को कहा गया। इसके अलावा पंचायती राज विभाग को जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों के आधार पर नए अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण, पंचायत भवनों का सुदृढ़ीकरण और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता और उपयोगिता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया, वहीं नगर निकायों को अपनी भूमि पर मैरिज हॉल, डिजिटल लाइब्रेरी और मल्टीपरपज हॉल का निर्माण कर राजस्व बढ़ाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए गए। जिला पूर्ति अधिकारी को रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने तथा पर्याप्त उपलब्धता की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि पेट्रोल पंपों की नियमित जांच की जा रही है और अवैध बिक्री पर रोक के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। बैठक के दौरान अनुपस्थित खनन अधिकारी के विरुद्ध सात दिन के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा 15 दिन में खनन कार्यों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक, जयपाल सिंह, पुलिस अधीक्षक केशव कुमार, मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अंत में जिलाधिकारी ने समिति का आभार व्यक्त करते हुए सभी निर्देशों के अक्षरशः अनुपालन का आश्वासन दिया।

गोरखपुर रोड स्थित ओवर ब्रिज की मरम्मत टली, मथुरा से नहीं पहुंची सामग्री, अब एक अप्रैल से शुरू होगा काम

देवरिया।

शहर के व्यस्ततम मार्गों में शामिल गोरखपुर रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज की मरम्मत का कार्य अब अगले सप्ताह शुरू होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों ने इस संबंध में प्रशासन को सूचना दे दी है। मरम्मत कार्य के लिए यातायात डायवर्जन भी उसी समय लागू किया जाएगा। ओवरब्रिज की मरम्मत के लिए पहले 27 मार्च से 22 अप्रैल तक का समय तय किया गया था। इस अवधि के लिए ओवरब्रिज को वन वे करने के लिए रूट डायवर्जन की योजना बनाई गई थी। शुक्रवार को काम शुरू करने से पहले उपलब्ध सामग्री की समीक्षा की गई तो पता चला कि मथुरा से आने वाली कुछ सामग्री के देवरिया पहुंचने में अभी तीन से चार दिन का और समय लगेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के सहायक अभियंता एमडी राय ने बताया कि

27 मार्च से शुरू होने वाला कार्य अब एक अप्रैल से शुरू करने की तैयारी

सभी आवश्यक उपकरण और निर्माण सामग्री पूरी तरह उपलब्ध होने के बाद ही काम शुरू किया जाएगा, ताकि बीच में कार्य बाधित न हो। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल से मरम्मत कार्य शुरू करने की तैयारी चल रही है। पूरी उम्मीद है कि तब तक सभी सामग्री आ जाएगी और काम शुरू कराया जा सकेगा। मरम्मत कार्य शुरू होने के साथ ही पुल पर यातायात का डायवर्जन भी लागू कर दिया जाएगा। डायवर्जन लागू होने के बाद भारी वाहनों के साथ ही अन्य वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से होकर गुजरना पड़ेगा। प्रशासन भी इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था की तैयारी में जुट गया है। मरम्मत कार्य शुरू होने के बाद यहां यातायात का दबाव अन्य मार्गों पर बढ़ सकता है। इसे देखते हुए प्रशासन ट्रैफिक प्रबंधन की रूपरेखा तैयार कर रहा है। मरम्मत कार्य के दौरान पुल के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत की जाएगी और संरचना को सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी तकनीकी कार्य किए जाएंगे। पुल की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यह कार्य अत्यंत आवश्यक बताया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि डायवर्जन लागू होने से पहले आम लोगों को इसकी जानकारी दे दी जाएगी, ताकि यात्रियों और वाहन चालकों को असुविधा कम से कम हो। साथ ही यातायात पुलिस को भी व्यवस्था संभालने के लिए तैनात किया जाएगा। यह पुल शहर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी मरम्मत के बाद यातायात की सुगमता और भी बढ़ जाएगी।

पडरौना में रामनवमी पर विशाल भंडारा, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

पडरौना, कुशीनगर।

चैत्र रामनवमी के पावन अवसर पर शुक्रवार को शहर के सुभाष चौक, एच.पी. पेट्रोल पंप के सामने भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माता रानी का प्रसाद ग्रहण किया और पुण्य लाभ अर्जित किया। दोपहर तीन बजे से शुरू हुए इस आयोजन में पूरे क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय हो गया, जहां जय माता दी के जयकारों से माहौल गूंज उठा। आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सुव्यवस्थित तरीके से प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई थी। स्थानीय लोगों के साथ-साथ दूर-दराज से आए भक्तों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। भंडारे में सामाजिक

समरसता और सेवा भावना का अद्भुत उदाहरण देखने को मिला, जहां सभी वर्गों के लोग एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते नजर आए। इस पुनीत आयोजन का नेतृत्व डॉ. कमलेश वर्मा एवं डॉ. पल्लवी सिंह द्वारा किया गया, जिनके प्रयासों से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन समाज में एकता और भाईचारे को मजबूत करते हैं।

लक्ष्मीपुर दुबे टोला काली मंदिर में हवन-पूजन व भंडारे के साथ रामनवमी संपन्न

नेबुआ नौरंगिया। क्षेत्र के लक्ष्मीपुर (नेबुआ रायगंज) स्थित दुबे टोला काली मंदिर पर रामनवमी के अवसर पर शुक्रवार को श्रद्धा और आस्था का भव्य आयोजन किया गया। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल देखने को मिला, जहां सुबह से ही दुर्गा मंदिरों और काली स्थानों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।नवरात्र के समापन के अवसर पर गुरुवार रात्रि में महिलाओं ने विधि-विधान से निशा पूजा कर कढ़ाई चढ़ाने की तैयारी की। शुक्रवार भोर होते ही श्रद्धालु मंदिरों और काली माता के स्थान पर पहुंचने लगे। महिलाओं ने श्रद्धा पूर्वक हलवा-पूरी का प्रसाद चढ़ाकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।इस अवसर पर राजेश श्रीवास्तव, मंदिर के पुजारी नथुनी राजभर एवं राजन भारती के नेतृत्व में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में गांव के सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रधान संघ के उपाध्यक्ष धीरज तिवारी, शंभू पांडेय, दीपक मद्धेशिया,सीतबसंत राय, अंकित मद्धेशिया सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे।

रामनवमी पर बुढ़िया माता मंदिर में विशाल भंडारा, 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

पडरौना, कुशीनगर।

नगर की मानस कॉलोनी स्थित प्राचीन श्री बुढ़िया माता मंदिर परिसर में रामनवमी के पावन अवसर पर विशाल भंडारे का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं ने सहभागिता करते हुए प्रसाद ग्रहण किया। जानकारी के अनुसार, यह धार्मिक आयोजन पिछले लगभग 20 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है, जिससे यह स्थान क्षेत्र की आस्था और परंपरा का प्रमुख केंद्र बन चुका है। हर वर्ष की तरह इस बार भी भंडारे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। आसपास के गांवों से लेकर दूरदराज क्षेत्रों तक के 5000 से अधिक भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। मंदिर के मुख्य पुजारी महंत वीरेंद दास जी महाराज ने इस अवसर पर माता के प्राकट्य का इतिहास बताते हुए कहा कि प्राचीन काल में मां को बंजारों की वनदेवी के रूप में पूजा जाता था। समय के साथ यह स्थान श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र बन गया। उन्होंने बताया कि मंदिर में प्रतिदिन विधि-विधान से पूजा-अर्चना होती है और यहां आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि मंदिर परिसर में माता की दिव्य शक्ति का विशेष अनुभव होता है, जो आध्यात्मिक शांति और संतोष प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि यहां सच्चे मन से आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण होती है। पूरे आयोजन के दौरान माता के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। भंडारे के सफल आयोजन में नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष बुलबुल जायसवाल, सुनील चौहान, अरविंद कुशवाहा, बृजेश शर्मा, रामू पाण्डेय, रीता कुशवाहा, मंजू चौधरी, अनीता देवी, अभय मारोदिया, रोहन विश्वकर्मा, आकाश वर्मा, जयप्रकाश मद्धेशिया, सीमा गुप्ता, अराध्या पाण्डेय, सोनल मिश्रा, नीलम देवी, अंजू देवी, प्रकाश राजभर, अतुल पाण्डेय, नगीना तिवारी सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

पेट्रोल-डीजल की पैनिक खरीदारी पर प्रशासन सख्त, गैरकानूनी भंडारण करने वालों पर होगी कार्रवाई

देवरिया। पिछले कुछ दिनों से जनपद के पेट्रोल पंपों पर अचानक पेट्रोल और डीजल की पैनिक खरीदारी शुरू हो गई है। लोगों द्वारा घबराकर की जा रही इस खरीदारी को देखते हुए जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार पांडेय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि जनपद में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और तेल कंपनियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जा रही है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि पैनिक खरीदारी की आड़ में किसी भी व्यक्ति द्वारा पेट्रोल व डीजल का गैरकानूनी भंडारण न किया जा सके, इसके लिए सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। पंपसेट, कंबाइन अथवा कृषि में प्रयोग होने वाले उपकरणों, निजी अस्पतालों एवं विद्यालयों के जनरेटर तथा मोबाइल टावर के जनरेटर हेतु पेट्रोल व डीजल की बिक्री गैलनों में की जा सकती है, लेकिन इसके लिए संबंधित कागजात की प्रति प्राप्त कर पंप कार्यालय में अनुरक्षित करना अनिवार्य होगा। पंप संचालकों को एक अलग रजिस्टर मेंटेन करना होगा, जिसमें उपभोक्ता

गैलन में बिक्री पर नियम सख्त, पंप संचालकों को रखना होगा उपभोक्ताओं का रजिस्टर

का नाम, मोबाइल नंबर, पता तथा प्राप्त किए गए कागजात का विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को उत्तर प्रदेश हाई स्पीड डीजल कंट्रोल ऑर्डर 1981 (यथासंशोधित) में उल्लिखित नियमों का अक्षरश पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा न होने पाए जाने पर नियमानुसार दंडात्मक विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के सभी नागरिकों को पुन सूचित किया है कि वर्तमान में जनपद में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जा रही है। तेल कंपनियों द्वारा नियमित रूप से सप्लाई जारी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक खरीदारी करने से बचें। किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना मिलने पर प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

आए थे रोजी-रोटी कमाने, खाने पर ही आ गया संकट, यूपी-बिहार-बंगाल के प्रवासी बोले- आ अब लौट चलें

नई दिल्ली । घर से हजारों किलोमीटर दूर प्रवासी रोजी-रोटी की जुगाड़ में निकले थे। अब एलपीजी किल्लत से उनके खाने पर ही संकट छा गया। इससे प्रवासी मजदूर अब बोल रहे, आ अब लौट चलें। इन दिनों भारी संख्या में प्रवासी अपने घर जाने के लिए दूसरे प्रदेशों समेत दिल्ली से रेलवे स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं। इससे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों से रोजी-रोटी की तलाश में आए लोगों पर गैस संकट से खाने पर भी संकट छा गया है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र भी अछूते नहीं है। तभी आनंद विहार, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घर लौटने वाले प्रवासियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रवासी किसी तरह अपने गांव लौटने को बेताब दिख रहे हैं।

एक किलो गैस के लिए देना पड़ रहा 600-800 रुपये

कटिहार, बिहार निवासी बिपिन कुमार ने बताया कि वह बाहरी दिल्ली के एक होटल में खाना बनाने का काम करते हैं। गैस की किल्लत के कारण उनका होटल बंद हो गया जिससे उनका रोजगार खत्म गया। घर में जो गैस बचे थे, वो भी खत्म हो गया है। बाजारों में एक किलो गैस भरने के लिए 600 से 800 रुपये मांगते हैं। रोजगार खत्म होने की वजह से उनके सामने हालात इतने बदतर हो गए कि घर का किराया तक जुटाना मुश्किल हो गया। इस स्थिति में अपने गांव लौटना ही ठीक समझा।

नहीं इतना पैसा कि रोज बाहर खाना खा सकें

इसी तरह दिल्ली के राजेंद्र नगर में रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले दरभंगा, बिहार निवासी सुमित यादव ने बताया कि घर में गैस खत्म हो गया है। उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि रोजाना बाहर खाना खा सकें। ऐसे में उन्होंने घर जाना ही ठीक समझा।

दिहाड़ी से अधिक गैस की कीमत

उत्तर प्रदेश निवासी सलमान अली ने बताया कि दिल्ली में रहकर पहले से ही दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब गैस की किल्लत और कालाबाजारी ने उनकी कमर तोड़ दी। उन्होंने बताया कि उनकी कमाई प्रतिदिन 300-400 रुपये होती है और गैस की कीमत बाजारों में 600-800 रुपये प्रति किलो है। इस हिसाब से उनका दिल्ली में रहकर गुजारा करना नामुमकिन है।

बंगाल में चुनाव है, वहां तो दिक्कत नहीं होगी

दिल्ली में एलपीजी गैस संकट का सामना कर रहे पश्चिम बंगाल के लोगों में वापसी का दूसरी वजह भी देखी गई। उनका कहना था कि दिल्ली में खाने के लाले पड़ रहे हैं, लेकिन उनके गृह राज्य में चुनावी साल होने से तोहफों की भरमार है।

सरकार वहां गैस की किल्लत नहीं होने दे रही है और खाने-पीने की सुविधा भी भरपूर है। पश्चिम बंगाल वापस जा रहे नदीम ने बताया कि वहां जाने से वोट तो दे ही, चुनावों के दौरान कोई संकट भी नहीं रहेगा।

किराए का बोझ और दो वक्त की रोटी की जंग जारी

आनंद विहार स्टेशन पर अपनी पोटली बांधे खड़े छोटे लाल की आंखों में बेबसी साफ देखी गई। वह बताते हैं कि साहब, काम बंद है, मालिक ने हाथ खड़े कर दिए हैं। मकान मालिक किराया मांग रहा है, लेकिन यहां तो पेट भरने के लाले पड़े हैं। जब गैस ही नहीं मिलेगी तो खाना कहां बनाएंगे। बताया कि कम से कम गांव में सूखी रोटी तो नसीब होगी।

पलायन शौक नहीं मजबूरी बनी

दिल्ली में रहकर अपना जीवन यापन करना अब गरीब मजदूर प्रवासियों के लिए मुश्किल हो गया है। मजदूरों का भरोसा अब व्यवस्था से उठ गया है। ऐसे में गरीब और मजदूर लोगों के लिए पलायन शौक नहीं मजबूरी बन चुकी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर लंबी-लंबी लाइनें और अपनों के साथ सिसकते चेहरे यह बता रहे हैं कि महानगरों की चकाचौंध के पीछे का अंधेरा कितना गहरा है।

देश में नहीं लगेगा लॉकडाउन

सरकार ने कहा- एलपीजी प्रोडक्शन 40फीसदी बढ़ा

नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सभी रिफाइनरी 100 फीसदी और उससे याद्रा कैपेसिटी से ऑपरेट कर रही हैं। देश में एलपीजी प्रोडक्शन 40 फीसदी बढ़ा है। 14 मार्च से अबतक 30 हजार कॉमर्शियल एलपीजी दी जा चुकी है।

रेस्टोरेंट, ढाबों को तवज्जो दी गई है। यह जानकारी पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने दी है। आद सुबह सरकार के तीन मंत्रियों ने भी देश में लॉकडाउन लगने की बात को नकारा है। वहीं, पीएम मोदी आज शाम पश्चिम एशिया के हालात पर सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। इधर, केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर नजर रखने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी का गठन किया है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ अन्य मंत्री शामिल है।

कीमतें बढ़ीं, सप्लाई प्रभावित- पश्चिम एशिया के संघर्ष से क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम उत्पाद महंगे हुए, सप्लाई चेन पर असर पड़ा।

भारत के पास पर्याप्त स्टॉक - देश में अगले 2 महीनों के लिए कच्चा तेल उपलब्ध है, LPG, LNG और PNG की सप्लाई भी फिलहाल सुरक्षित है।

आयात पर ज्यादा निर्भरता- भारत लगभग 90फीसदी एलपीजी आयात करता है, जो ज्यादातर होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते आता है।

घरेलू जरूरत को प्राथमिकता- सरकार ने पहले कमर्शियल सप्लाई घटाई, फिर धीरे-धीरे बढ़ाकर अब 70 फीसदी तक कर दी। 14 मार्च से अब तक 30,000 टन एलपीजी सप्लाई की गई।

अफवाहों से पंपों पर भीड़ - कुछ जगहों पर लंबी कतारें दिखीं, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल-डीजल या गैस की कोई कमी नहीं है।

लेह में सात की मौत- पहाड़ से गिरा बर्फ का बड़ा हिस्सा, नीचे से गुजर रही थीं गाड़ियां

कारगिल । लद्दाख के कारगिल जिले में जोजिला-गुमरी मार्ग पर शुक्रवार दोपहर प्रकृति का कहर टूटा। जीरो पॉइंट और मिनीमर्ग के बीच भारी हिमस्खलन ने कई जिंदगियों को चपेट में ले लिया। हादसे में सात लोगों की मौत हो गई। कम से कम पांच लोग गंभीर घायल हुए हैं। बर्फ के विशाल मलबे के नीचे 7 से 8 वाहनों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्र लेह-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है। शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे वाहन जोजिला दर्रे से गुजर रहे थे। इसी दौरान पहाड़ों पर भूस्खलन हुआ और बर्फ का बड़ा हिस्सा तेजी से सड़क पर आ गिरा। पलक झपकते ही वाहन बर्फ के नीचे दब गए। सूचना मिलते ही सेना, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), लद्दाख पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें बचाव एवं राहत कार्य के लिए मशीनों के साथ पहुंच गईं। खराब मौसम और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद देर रात तक सेना और बीआरओ के जवान स्थानीय स्वयंसेवकों की मदद से बर्फ हटाने और फंसे हुए लोगों को निकालने के कार्य में जुटे थे। घायलों को तत्काल निकालने के लिए बसीज इमाम खामनेई मेमोरियल ट्रस्ट (आईकेएमटी) के सदस्य और 108 एम्बुलेंस तैनात है। केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भूस्खलन में दबने से सात लोगों की मौत की पुष्टि की है। अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट में उन्होंने बताया कि हादसे में पांच लोग घायल हुए हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की है। सभी घायलों को उप-जिला अस्पताल द्रास में भर्ती कराया गया है। चार की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों और मृतकों में अधिकतर लेह जिले के हैं। हिमस्खलन की जो तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, उनसे हादसे की वीभत्सता नजर आती है। वाहन बर्फ में पूरी तरह दब गए हैं। वाहनों की छत से बर्फ हटाने में ही सेना और बीआरओ के जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जहां पर हादसा हुआ वहां सड़क पहाड़ी एवं दुर्गम है। घटना स्थल पर एक तरफ सीधी खड़ी पहाड़ी है तो दूसरी तरफ खाई। ऐसे में जवानों को हर कदम सावधानी से बढ़ना पड़ रहा है। जोजिला क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार हिमस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। शुक्रवार का हादसा बड़ा और घातक साबित हुआ। रास्ते पर भारी बर्फ जमी है। फिलहाल मार्ग पर यातायात पूरी तरह रोक दिया गया है। बचाव दल का प्राथमिक लक्ष्य फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालना और उसके बाद सड़क को दोबारा वाहनों के लिए सुचारू करना है।

चाचा ने अपने सगे भाई के तीन बच्चों की हत्या

बिहार के औरंगाबाद से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। हसपुरा थाना क्षेत्र के खुटहन गांव में एक युवक ने मामूली बात पर हुए विवाद के बाद अपने सगे भाई के तीन बच्चों की हत्या कर दी। मृतकों में 10 वर्षीय अनीश, 7 वर्षीय आयुष और 5 वर्षीय अनुष्का शामिल है। जानकारी के अनुसार, आरोपी अमित पाल शुक्रवार सुबह कहीं बाहर गया था। वापस लौटने पर उसने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उस वक्त उसकी भाभी स्नान कर रही थीं, जिस कारण दरवाजा खोलने में थोड़ी देर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इसी बात से तैश में आकर अमित हैवानियत पर उतारू हो गया। वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी ने कमरे में रखे स्पीकर की आवाज फुल कर दी, ताकि बच्चों की चीखें बाहर न जा सकें। इसके बाद उसने बारी-बारी से तीनों मासूमों का गला रेत दिया। घटना का पता तब चला जब कमरे का दरवाजा खुला। अंदर का मंजर देख लोगों की रूह कांप गई। तीनों बच्चों के शव एक ही जगह खून से लथपथ पड़े थे। पास ही आरोपी अमित पाल भी तड़प रहा था, जिसने बच्चों की हत्या के बाद उसी हथियार से अपना भी गला काट लिया था।

तेज रफ्तार एसयूवी ने ऑटो-रिक्शा को टक्कर मारी, पांच लोगों की मौत व चार घायल

ग्वालियर । मध्यप्रदेश के ग्वालियर में शुक्रवार तड़के पुलिस के पीछा किए जाने के दौरान तेज रफ्तार एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) ने एक ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी जिससे एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि दो बच्चों सहित चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि टक्कर की एक अन्य घटना में शामिल होने के बाद भागने की कोशिश कर रहे एसयूवी के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।ग्वालियर जोन के पुलिस महानिरीक्षक अरविंद सक्सेना के मुताबिक, यह हादसा तड़के करीब पौने तीन बजे परशुराम चौराहा पर हुआ। रामनवमी के अवसर पर शीतला माता मंदिर में दर्शन के बाद ऑटो-रिक्शा से लौट रहे थे।

मिडिल ईस्ट संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुआ इंटर-मिनिस्ट्रियल ग्रुप का गठन

नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे तनावपूर्ण संघर्ष ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। ऐसे में भारत सरकार ने कदम उठाते हुए एक अहम फैसला लिया है।

केंद्र सरकार ने मिडिल ईस्ट संकट से पैदा होने वाले विभिन्न मुद्दों पर लगातार नजर रखने और उनका समाधान करने के लिए एक इंटर-मिनिस्ट्रियल ग्रुप का गठन किया है। इस ग्रुप की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। ग्रुप में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अन्य संबंधित मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हैं। यह ग्रुप मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध से भारत पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों खासकर ऊर्जा सुरक्षा, तेल-गैस आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता पर नजर रखेगा। सरकार का यह कदम इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि भारत अपनी कच्चे तेल की लगभग 88 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस की आधी जरूरत होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आयात करता है। हाल के हमलों के बाद इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने से टैंकरों की आवाजाही पर असर हुआ है, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा गया है। भारत में ईंधन की कीमतों में उछाल या पैनिक स्थिति न बने, इसके लिए यह ग्रुप एक्टिव रूप से काम करेगा। इसी क्रम में सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर शून्य कर दी है। डीजल निर्यात पर लगने वाले लाभ कर और जेट फ्यूल पर करों में भी संशोधन किया गया है। केंद्र ने लॉकडाउन लगाए जाने की अफवाहों को भी सिरे से खारिज कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई मंत्रियों ने साफ कहा कि देश में कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। जनता से पैनिक न फैलाने की अपील की गई है। राजनाथ सिंह की अगुवाई वाला यह इंटर-मिनिस्ट्रियल ग्रुप देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए निरंतर निगरानी रखेगा।

अमेरिका से जमीनी लड़ाई की तैयारी, सेना में युवाओं की भर्ती हुई तेज

रिपोर्ट- ईरान में जंग के लिए 10 लाख सैनिक तैयार

तेहरान। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने 10 लाख से ज्यादा ग्राउंड सैनिक जुटाने का दावा किया है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका जमीनी हमला कर सकता है। इसके चलते युवाओं में सेना में भर्ती की होड़ बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के दिनों में बड़ी संख्या में युवा बसीज, रिवोल्यूशनरी गार्ड और सेना में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे हैं। वहीं, अमेरिका मिडिल ईस्ट में करीब 10,000 एक्स्ट्रा सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा विभाग के

अधिकारियों ने बताया कि इस फोर्स में पैदल सेना और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हो सकती हैं। यह एक्स्ट्रा सैनिक मिडिल ईस्ट में पहले से मौजूद 5,000 मरीन और 2,000 पैराट्रूपर्स के साथ जोड़े जाएंगे। ये पैराट्रूपर्स 82वीं एयरबोर्न डिवीजन से हैं।

ईरान का दावा- होर्मुज स्ट्रेट से 3 जहाज लौटाए

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे तीन जहाजों को वापस लौटा दिया। सेपाह न्यूज के हवाले से आईआरजीसी ने कहा कि ये जहाज अलग-अलग देशों के थे और चेतावनी देने के बाद इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया। आईआरजीसी के मुताबिक, यह मार्ग अब उन जहाजों के लिए बंद कर दिया गया है जो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बंदरगाहों से आते या जाते हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि ऐसे जहाजों की आवाजाही, चाहे वे किसी भी रास्ते से गुजरने की कोशिश करें, पूरी

किसी भी जहाज को नहीं गुजरने देंगे, आईआरजीसी ने बंद किया होर्मुज स्ट्रेट; यूएस-इजरायल को दी चेतावनी

तरह प्रतिबंधित कर दी गई है।

अमेरिका ने 850 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें दागीं

अमेरिका के रक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों के हवाले से आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने ईरान के साथ जारी युद्ध के चार हफ्तों में 850 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट के अनुसार, इतनी तेजी से इन सटीक मिसाइलों के इस्तेमाल ने पेंटागन के कुछ अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है और अब इनके भंडार को बढ़ाने पर अंदरूनी चर्चा चल रही है।

हाईवे किनारे खड़े ट्राला से भिड़ा वाहन, सात श्रद्धालुओं की मौत

कौशांबी। कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर डोरमा पेट्रोल पंप के समीप सड़क किनारे खड़े ट्राला में सैनी की तरफ से जा रही पिकअप अनियंत्रित होकर पीछे से टकरा गई। हादसे में पिकअप के परखचे उड़े गए। पिकअप में सवार रहे महिलाओं, बच्चों समेत 25 लोगों में सात की इलाज के लिए जाते वक्त मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिकअप सवार सभी लोग फतेहपुर जिले के मलवा क्षेत्र के बड़ौरवार गांव निवासी हैं। वह लोग पिकअप बुक करके शुक्रवार की सुबह रामनवमी के अवसर पर कड़ा धाम स्थित मां शीतला का दर्शन करने आए थे। लौटते समय शुक्रवार दोपहर करीब पौने चार बजे हादसा हुआ। सड़क पर घायलों की चीत्कार मची रही।

पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक - राज्यों को सप्लाई चेन दुरुस्त रखने के निर्देश, टीम इंडिया की भावना पर जोर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। यह बैठक डिजिटल माध्यम से हुई। बैठक में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा की गई। आदर्श आचार संहिता के कारण चुनावी राज्य इस बैठक में शामिल नहीं हुए। चुनावी राज्यों के मुख्य सचिवों के लिए एक अलग बैठक होगी, जो कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से की जाएगी।

बैठक में प्रधानमंत्री ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि टीम इंडिया की भावना से मिलकर काम करने पर देश इस स्थिति से सफलतापूर्वक उबर जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की प्राथमिकताएं आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, नागरिकों के हितों की रक्षा करना और उद्योग व आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है।

उन्होंने राज्यों से आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने और जमाखोरी व मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में अग्रिम योजना बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया, खासकर उर्वरक भंडारण और वितरण की निगरानी में। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी स्तरों पर मजबूत समन्वय तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि बदलते हालात में तत्काल प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने सीमा और तटीय राज्यों में खास ध्यान देने का निर्देश दिया, ताकि नौवहन, आवश्यक आपूर्ति और समुद्री संचालन से जुड़ी नई चुनौतियों का समाधान किया जा सके। प्रधानमंत्री ने गलत सूचनाओं व अफवाहों से सतर्क रहने का भी आग्रह किया और सही व विश्वसनीय जानकारी फैलाने पर जोर दिया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, डिजिटल माध्यम से यह बैठक टीम इंडिया की भावना के तहत राज्यों और केंद्र के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। यह पहली बार है, जब प्रधानमंत्री ने 28 फरवरी को अमेरिका-इजराइल के ईरान पर हमले से शुरू हुए पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ इस तरह की बैठक की। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने खाड़ी पड़ोसी देशों और इजराइल पर हमले किए।

बैठक में कौन-कौन मुख्यमंत्री शामिल हुए?

बैठक में आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, पंजाब के भगवंत मान, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, जम्मू-कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू

और अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू सहित कई मुख्यमंत्री शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद थे। एक सूत्र ने बताया, प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और राज्यों की तैयारियों व योजनाओं की समीक्षा की। बैठक का फोकस टीम इंडिया की भावना के तहत तालमेल सुनिश्चित करना था। आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव वाले राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए। कैबिनेट सचिवालय चुनाव वाले राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्य सचिवों के साथ अलग बैठक करेगा।

मुख्यमंत्रियों ने बैठक में क्या कहा?

वहीं, मुख्यमंत्रियों ने स्थिति से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। उन्होंने वैश्विक अनिश्चितता के बीच ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम करने और राज्यों को वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन बढ़ाने के फैसलों का स्वागत किया। मुख्यमंत्रियों ने भरोसा जताया कि उनके राज्यों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता के कारण स्तिति स्थिर बनी हुई है। उसी दिन एक मीडिया कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद भी चुनौतियां लगातार बढ़ती रही हैं और ऐसा कोई साल नहीं रहा जब भारत और भारतीयों की परीक्षा न हुई हो। लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के संयुक्त प्रयास से भारत हर आपदा का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और चुनौतियों को टालने के बजाय सीधे उनका सामना कर रहा है।

संकट पर पहले हुई थी सर्वदलीय बैठक

सरकार ने 25 मार्च को पश्चिम एशिया की स्थिति पर राजनीतिक दलों के नेताओं को जानकारी देने के लिए सर्वदलीय बैठक भी की थी, जिसमें स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी दी गई। 23 मार्च को लोकसभा में बयान देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि पश्चिम एशिया संघर्ष से पैदा हुई वैश्विक परिस्थितियां लंबे समय तक बनी रह सकती हैं और उन्होंने देश से एकजुट और तैयार रहने का आह्वान किया था, जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान रहा था। उन्होंने संकट के आंतरिक सुरक्षा पहलू की ओर भी ध्यान दिलाते हुए कहा कि कुछ तत्व ऐसी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है और तटीय, सीमा, साइबर और रणनीतिक ठिकानों की सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा, चाहे तटीय सुरक्षा हो, सीमा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा या रणनीतिक प्रतिष्ठान, सभी की सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। पीएम मोदी ने धैर्य, संयम और सतर्कता बरतने की अपील की और अफवाह फैलाने, कालाबाजारी या जमाखोरी करने वालों के खिलाफ चेतावनी दी और सभी राज्य सरकारों से सख्त निगरानी और तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। लोकसभा में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश की सामूहिक ताकत पर भरोसा जताते हुए कहा कि जब देश की हर सरकार और हर नागरिक साथ चलता है, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, यही हमारी पहचान और ताकत है। मुख्यमंत्रियों ने भरोसा जताया कि उनके राज्यों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता के कारण स्थिति स्थिर बनी हुई है। साथ ही, उन्होंने केंद्र के साथ मिलकर प्रभावी प्रबंधन के लिए तालमेल बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।